



2026:AHC:125360-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 23182 वर्ष 2026

अंजू शुक्ला..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राहुल कुमार त्रिपाठी, शिशिर कुमार द्विवेदी, श्रुति द्विवेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 39

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री शिशिर कुमार द्विवेदी और राज्य के स्थायी अधिवक्ता श्री गिरीश चंद तिवारी को सुना।
2. प्रस्तुत याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

I. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक सहायक दस्तावेजों के आधार पर प्रतिपक्षी अधिकारियों को उसके आधार कार्ड में याचिकाकर्ता के नाम को "मंजू शुक्ला" से "अंजू शुक्ला" तक सही करने का आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;

II. प्रतिपक्षी अधिकारियों को आधार कार्ड में नाम में सुधार के लिए याचिकाकर्ता के दिनांक 15.05.2026 (अनुलग्नक-6) के अभ्यावेदन/आवेदन पर विचार करने और



निर्णय लेने का आदेश देते हुए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ता को उसके द्वारा पीड़ित स्तन कैंसर के निदान के कारण प्रस्तुत शिकायत उत्पन्न हुई है। वह सरकार की एक कल्याणकारी योजना का लाभ उठाना चाहती है, जिसके उद्देश्य के लिए दस्तावेज सत्यापन - अपनी सही पहचान स्थापित करने की आवश्यकता है।

4. उस अप्रत्याशित परिस्थिति में, याचिकाकर्ता केवल इस कारण से राज्य की कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने में असमर्थ है कि यद्यपि उसका नाम 'अंजू शुक्ला' है, अनजाने के कारण, उसका नाम आधार कार्ड में 'मंजू देवी' के रूप में दर्ज किया गया था। केवल इसी कारण से, वह राज्य की कल्याण योजना के तहत खुद को पंजीकृत करने में असमर्थ है - जो उसके भारी चिकित्सा खर्चों के लिए प्रदान कर सकती है। विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां रिट याचिका के साथ संलग्न की गई हैं।

5. साथ ही, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के जूनियर उच्च स्कूल प्रमाण पत्र की प्रति अभिलेखों पर रखी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा इस पर हस्ताक्षर और सत्यापन किया गया है और इसे 'एक्स' के रूप में चिह्नित किया गया है और अभिलेखों पर रखा गया है।

6. इस प्रकार, यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता श्रीमती अंजू शुक्ला ने 1987 में जूनियर उच्च स्कूल पास किया, जिसमें उनके पहले नाम 'कु० अंजू देवी' ने अपने पिता का नाम 'आत्मा प्रसाद मिश्रा' और उनकी जन्मतिथि '27.04.1974' का खुलासा किया। फिर, 27.08.1989 को, याचिकाकर्ता ने उच्च स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय तक, वह शादीशुदा थी। इस प्रकार, उच्च स्कूल के प्रमाण पत्र में उसका नाम 'श्रीमती अंजू देवी' के रूप में प्रकट किया गया था। उन्हें जारी किए गए पैन कार्ड 'FDTPXXXXXXXX' में उनका नाम 'अंजू शुक्ला' बताया गया है, जो 'आत्मा प्रसाद मिश्रा' की बेटी है। उनके वोटर आई.डी. कार्ड पर उनका नाम 'लक्ष्मी कांता' की पत्नी 'अंजू' बताया गया है। 'लक्ष्मी कांत शुक्ला' के राशन कार्ड में याचिकाकर्ता को उनकी पत्नी के रूप में 'श्रीमती अंजू शुक्ला' नाम से शामिल किया गया है। फिर, उसका आधार कार्ड '6511XXXXXXXX' उसका नाम 'मंजू' के रूप में प्रकट करता है।



7. एक ही समय में: (i) आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड और पैन कार्ड पर फोटो प्रथम दृष्टया एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। (ii) पैन कार्ड में दर्ज उसकी जन्म-तारीख जूनियर उच्च स्कूल प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि के साथ-साथ उच्च स्कूल प्रमाणपत्र से भी मेल खाती है। (iii) जहां तक उसके पिता के नाम का संबंध है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि वह श्री आत्मा प्रसाद मिश्र की बेटी है, जैसा कि पैन कार्ड में दर्ज है और साथ ही जूनियर उच्च स्कूल की अंक पत्र में भी दर्ज है, जिसे आज प्रस्तुत किया गया है। (iv) मतदाता पहचान पत्र पर लक्ष्मी कांत के रूप में दर्ज उनके पति लक्ष्मी कांत शुक्ला का नाम वही नाम है जो राशन कार्ड पर दिखाई देता है।
8. इस हद तक, उपरोक्त तथ्य निर्विवाद हैं और आगे के रूप में आधार कार्ड के संबंध में बायो-मेट्रिक्स उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के आधार कार्ड को बायो-मीट्रिक मिलान के बाद उसके पैन कार्ड के संदर्भ में ठीक किया जा सकता है, जिसे ऊपर उल्लिखित किया गया है।
9. तदनुसार, संलग्न निर्देशों के आलोक में, वर्तमान याचिका का निम्नलिखित टिप्पणी के साथ निस्तारण किया जाता है कि, यदि याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रति प्रतिवादी संख्या 3/जिलाधिकारी, संत रविदास नगर, भदोही के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो उक्त प्राधिकारी भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) तथा/अथवा जनपद में उपलब्ध सक्षम अभिकरण को, इस आदेश के अनुपालन में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन सम्मिलित किए जाने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी कर सकेगा। ऐसे आवश्यक संशोधन/परिवर्तन, याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किए जाने तथा निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त प्राधिकारी/अभिकरण के समक्ष उपस्थित होने की शर्त के अधीन, आज से 1 सप्ताह की अवधि के भीतर किए जाएंगे।

(न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह)

(न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

4 जून 2026 / प्रखर